© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
https://www.eurekajournals.com/shodh.html
ISSN: 2581-3501

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के औद्योगिक और आर्थिक विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अजय कृष्ण तिवारी[1]

शिक्षाविद एवं अर्थशास्त्री और पीएच.डी. मार्गदर्शक।

अमूर्त

इस शोध पत्र को लिखने का उद्देश्य नेताजी की उस तीव्र आर्थिक सोच पर मंथन करना है जिसने कभी भारत को विकसित देशों में शीर्ष पर पहुंचानेमेंनेता की आर्थिक सोच की श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्वोत्तम निर्यातक होते, आयातक नहीं, P.O.K, अक्साई चीन का अस्तित्व ही नहीं होता - शायद पाकिस्तान, बर्मा और बांग्लादेश अलग राष्ट्र नहीं होते, न ही कोई भेदभाव होता, यदि होते तीव्र आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक विकास होता तो आज हम सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे होते - हम पहले ही कर चुके होते। क्या यह डॉलर के बराबर या उससे नीचे होगा? इस पर मंथन जरूरी है. विशेष लेख आज उनके 126वें जन्मदिन पर है. यह वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में नेता की आर्थिक सोच की श्रेष्ठता को सिद्ध करता है।

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

परिचय

कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए सुभाष चंद्र बोस को यह अहसास हो गया था कि आजादी अब ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वतंत्र भारत की सरकार के बारे में सोचते समय योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रथम कदम के रूप में 'राष्ट्रीय योजना समिति' का गठन किया गया। अक्टूबर 1946 में, अंतरिम सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार योजना बोर्ड की स्थापना की गई, जिससे स्वतंत्र भारत में योजना आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में नेता की आर्थिक सोच की श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। सिद्धार्थ मुखर्जी: नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता आंदोलन और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तो चर्चा होती है, लेकिन उनके घटनापूर्ण जीवन के दूसरे पहलू पर उतनी चर्चा नहीं होती. वह, उनके औद्योगिक और आर्थिक विचार। एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में, नेताजी ने एक बार खुद ही जमशेदपुर में टाटा स्टील फैक्ट्री में हड़ताल को संभाला था। वह भारत के 'राष्ट्रीय योजना आयोग' के संस्थापक भी थे

Netaji Museum

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्थिक बुद्धि

1928 में जब सुभाष चन्द्र ने टाटा फैक्ट्री में हड़ताल ख़त्म की तो अधिकारी यह दावा करते दिखे कि उस फैक्ट्री में किसी भी कर्मचारी का असंतोष नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि 50 या 75 साल बाद भी यह औद्योगिक समूह यह दावा करता नजर आया है कि कारखाने में मालिक-मजदूर का सामंजस्य कायम है. हालाँकि प्रबंधन ने 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन के समर्थन में इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 'प्रतीकात्मक हड़ताल' का समर्थन किया था, लेकिन यह हड़ताल राजनीति से प्रेरित थी। परिणामस्वरूप, टाटा स्टील प्रबंधन ने 1928 की हड़ताल को आखिरी वास्तविक हड़ताल करार दिया है।

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्थिक नेतृत्व क्षमता

1928 से 1937 तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट के श्रमिक संघ के अध्यक्ष थे। 1920 में गठित उस यूनियन के तीसरे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा थे। उस समय वे टाटा के अधिकारियों से संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर विदेशियों को लाने और उनकी जगह लेने की मांग करने में सक्षम थे। तभी टाटा स्टील के तत्कालीन बॉस एन.बी.सुभाष चंद्रा ने सकलातवाला को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा, 'इस कंपनी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि शीर्ष पर कोई भारतीय नहीं है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि टाटा स्टील भारतीयकरण की नीति पर आगे बढ़ती है, तो आप भारतीय कर्मचारियों के साथ-साथ देश भर में विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं को भी अपना सकेंगे।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़े पैमाने और मशीन उद्योगों के माध्यम से औद्योगीकरण पर जोर देना चाहते थे

इसके तुरंत बाद टाटा स्टील को अपना पहला भारतीय महाप्रबंधक मिल गया। इसके अलावा, नेताजी श्रमिकों की मांग के अनुसार मातृत्व अवकाश और पहले लाभ-आधारित बोनस समझौते के लिए दबाव

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

डालने में सक्षम थे। इस बीच, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने जब अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं के दिमाग में भारत का औद्योगीकरण था। लेकिन प्रश्न यह उठा कि भारत में औद्योगीकरण कैसे होगा? जबकि कई नेताओं का झुकाव खादी और कुटीर उद्योगों की ओर था, सुभाष चंद्र भी बड़े पैमाने और मशीन उद्योगों के माध्यम से औद्योगीकरण पर जोर देना चाहते थे।

नेताजी ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं राष्ट्रीय आर्थिक विकास योजना का विचार दिया

फरवरी 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर सत्र में अपने अध्यक्षीय भाषण में, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का खाका तैयार किया, जिसने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय योजना का विचार दिया। 2 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में राज्यों के औद्योगिक मंत्रियों के एक सम्मेलन में दिए गए भाषण में नेताजी ने अपनी राष्ट्रीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस प्रकार नेताजी ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसका उद्घाटन उन्होंने 17 दिसंबर 1938 को बॉम्बे (अब मुंबई) में किया।

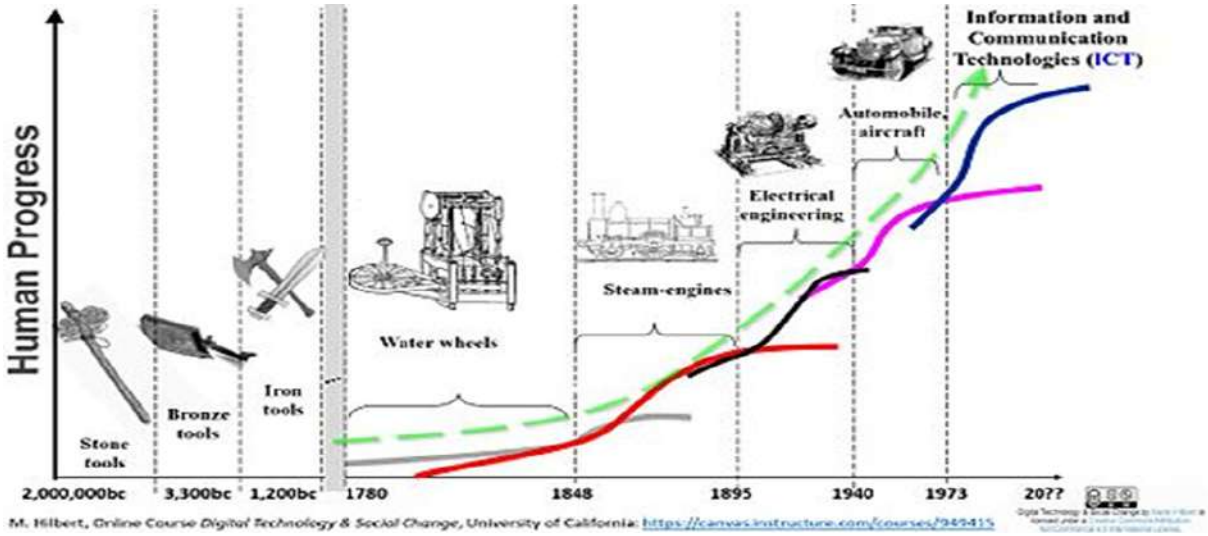

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

जब तक हम औद्योगिक क्रांति का मार्ग पार नहीं कर लेते तब तक कोई भी औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है।

लेकिन उससे पहले 21 अगस्त 1938 को नेता जी ने वैज्ञानिक मेघन आशा को समस्या समझायीराष्ट्रीय पुनर्निर्माण के एमएस ने कहा, 'हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं वह औद्योगीकरण है, औद्योगिक बहाली नहीं। भारत अभी भी पूर्व-औद्योगिक चरण में है। जब तक हम औद्योगिक क्रांति का मार्ग पार नहीं कर लेते तब तक कोई भी औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है। ... पहली बात तो यह तय करनी होगी कि क्या यह क्रांति, यानी औद्योगीकरण, ग्रेट ब्रिटेन की तरह क्रमिक विकास का मार्ग अपनाएगी, या मजबूरी का तीव्र मार्ग अपनाएगी। सोवियत रूस में।'

नेताजी सुभाष चन्द्र ने राष्ट्रीय आर्थिक विकास योजना समिति की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की

जुलाई 1938 में हरिपुर सत्र और उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति की मंजूरी के बाद, उन्होंने एक आधिकारिक मंच का उपयोग करते हु ए एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े संगठनात्मक ढांचे तक ही सीमित नहीं थी। उस समय उपमहाद्वीप ब्रिटिश भारत और भारतीय प्रभुत्व में विभाजित था। राष्ट्रीय नियोजन की अवधारणा के बारे मेंशामिल किया जाना चाहिए।

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

नेताजी के राष्ट्रपति बनने से पहले 1937 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति में केवल एक औद्योगिक योजना पर चर्चा की गई थी

जिसमें राष्ट्रीय नियोजन के विचार में सुभाष चन्द्र ने तेजी से औद्योगीकरण के साथ-साथ गरीबी और बेरोजगारी की आवश्यकता पर बल दिया। नेताजी का मानना था कि योजना प्रक्रिया में ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों के साथ-साथ सभी भारतीय राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जहां उन्होंने कांग्रेस शासित सात प्रांतों की सरकारों तक अपना दृष्टिकोण पहुंचाने की कोशिश की, वहीं उनका इरादा गैर-कांग्रेस शासित ब्रिटिश भारतीय राज्यों और भारतीय राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भी इस योजना के तहत लाने का था, ताकि इस प्रक्रिया के माध्यम से वे इसका हिस्सा बन सकें। भारत की। पुनर्निर्माण की योजना बनाने के लिए एक साथ आएं।

राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्निर्माण की नेताजी की अवधारणा का परिचय दिया।

राष्ट्रीय योजना समिति की पहली बैठक के लिए बम्बई को चुना गया। चूँकि बंबई से अपेक्षा की गई थी कि वह प्रांत की तत्कालीन सरकार को ढांचागत सहायता प्रदान करेगी। राष्ट्रीय योजना समिति की पहली बैठक का उद्घाटन नेताजी ने किया था और अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय नेताजी ने नेहरू को राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। 19 अक्टूबर 1938 को लिखे एक पत्र में नेताजी ने जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता की पेशकश की और लिखा, 'मुझे आशा है कि आप योजना समिति की अध्यक्षता स्वीकार करेंगे। इसे सफल बनाने के लिए आपको वहां मौजूद रहना होगा।'

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

सबको साथ लेकर भारत में योजना और औद्योगीकरण पर मंथन

कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेताजी स्वयं राष्ट्रीय योजना की ऐतिहासिक घटना के प्रथम अध्यक्ष एवं सूत्रधार हो सकते थे। लेकिन उन्होंने समझा कि योजना की सफलता के लिए आम सहमति जरूरी है। संयोगवश, जब सुभाष चंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, तब राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर पार्टी के भीतर वैचारिक मतभेद थे। उस स्थिति में, सुभाष चंद्रा खुद को पहली राष्ट्रीय योजना समिति के शीर्ष पर नहीं रखना चाहते थे, जिसने भारत में योजना और औद्योगीकरण के बीज बोए थे, भले ही यह मुख्य रूप से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी पहल थी जिसने समिति का नेतृत्व किया था। इसे बनाया

निष्कर्ष

जब सुभाष चन्द्र कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उन्हें यह अहसास हो गया था कि आजादी अब दूर नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वतंत्र भारत की सरकार के बारे में सोचते समय योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहले कदम के रूप में, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार योजना बोर्ड का गठन किया गया, जिससे स्वतंत्र भारत में योजना आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालाँकि, बाद में 2014 में मोदी सरकार ने 'योजना आयोग' को ख़त्म कर दिया। और उसके स्थान पर 'नीति आयोग' का गठन किया गया।

सन्दर्भ

अयेर, एस.ए., स्टोरी ऑफ़ द आई.एन.ए., नेशनल बुक, ट्रस्ट, नई दिल्ली, 1972.

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

आयर, एस.ए., अनटू हिम ए विटनेस, ठाकर एंड कंपनी बॉम्बे, 1951.

बनर्जी, सर सरेंडर, ए नेशन इन मेकिंग, कलकत्ता, 1925.

बोस, सिसल कुमार, एड., ए बीकन अक्रॉस एशिया, ए बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ओरिएंट लॉन्गमैन्स, नई दिल्ली, 1973.

बोस, एन.के., स्टडीज़ इन गांधीज़, न्युबियन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1972.

बोस, सुभाष चंद्र, नेताजी कलेक्टेड वर्क्स, वॉयड (एन इंडियन पिलग्रिम एंड लेटर्स 1912-1921), नेताजी रिसर्च ब्यूरो, कलकत्ता, 1980.

बोस, सुभाष चंद्र, नेताजी कलेक्टेड वर्क्स खंड II (द इंडियन स्ट्रगल 1920-42), नेताजी रिसर्च ब्यूरो, कलकत्ता, 1981.

बोस, सुभाष चंद्र, नेताजीज़ कलेक्टेड वर्क्स खंड VIII: लेख, भाषण और वक्तव्य 1933-1937, संस्करण।

सिसल कुमार बोस और सीगेट बोस, नेताजी रिसर्च ब्यूरो, कलकत्ता, 1994.

बोस, सुभाष चंद्र, नेताजी के एकत्रित कार्य खंड IX: कांग्रेस अध्यक्ष के, भाषण और लेख और पत्र, जनवरी 1938 - मई 1939 संस्करण। सिसल कुमार बोस और सीगेट बोस, नेताजी रिसर्च ब्यूरो, कलकत्ता, 1995.

बोस, सुभाष चंद्र, भारतीय क्रांति के मौलिक प्रश्न, नेताजी रिसर्च ब्यूरो, कलकत्ता, 1970.